दावोस

1. दावोस स्विटजरलैण्ड के उत्तर में स्थित एक छोटा सा शहर है जो दुनियाभर में मशहूर हो चुका है, हरवर्ष जनवरी के अंत में वहां आयोजित होने वाले एक अनोखे आर्थिक शिखर सम्मेलन के लिए। इस सम्मेलन का आयोजन पहले-पहल 1971 में किया गया था, तब किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि इतनी जल्दी अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में इतनी अहमियत हासिल कर लेगा।

2. इसके जन्मदाता थे जिनेवा बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट पढ़ाने वाले एक जर्मन प्रोफेसर क्लॉड श्वाब, जिनका सीमित उद्देश्य उस वक्त यूरोप की बड़ी-बड़ी कंपनियों के चोटी के प्रबंधकों के विचार-विमर्श और उनके बीच आपसी परामर्श के लिए एक तटस्थ मंच प्रस्तुत करना था। 1970 के दशक के आरंभ में यूरोपीय समुदाय ने अपनी स्पष्ट पहचान नहीं बनाई थी और एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में इसकी भूमिका के बारे में लोगों के मन में असमनजस थी। यह सोचना तर्कसंगत है कि इन आशंकाओं को दूर करने के लिये ही दावोस सम्मेलन का विचार श्वाब के मन में आया।

3. समय बीतने के साथ क्रमशः इसकी भूमिका में महत्वाकांक्षी विस्तार हुआ। भले ही यह एक ग़ैर सरकारी संगठन था स्विस सरकार ने इसको मान्यता देने में जरा भी देर नहीं लगाई। जहां तक स्विस सरकार का प्रश्न है वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में अपने राष्ट्रहित को किसी भी विचारधारा से बाधित नहीं होने देती। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उसकी भूमिका एक ऐसे तटस्थ देश की रही थी जिसने नाजियों और मित्र राष्ट्रों के बीच समान दूरी रखी थी। स्विस बैंकों की गोपनीयता दुनियाभर में मशहूर है। वह किसी भी खाताधारी का नाम, पता किसी जांचकर्ता को नहीं बताते और न ही धन जमा करने वाले से उसका स्रोत पूछते हैं। स्विस सरकार का प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी वित्तीय व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली केन्द्रीय भूमिका निभाये और उसका लाभांश उसे बिना कुछ किये हासिल हो जाए।

4. स्विटजरलैण्ड को संसार के सबसे सुन्दर और आकर्षक पयर्टक केन्द्रों में गिना जाता है और इसीलिए स्विटजरलैण्ड की सरकार अन्तर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के माध्यम से भी सरकारी अधिकारियों पत्रकारों आदि के जमावड़े के माध्यम से इस कारोबार को बढ़ाने का कोई मौका छोड़ती नहीं। जो अन्तर्राष्ट्रीय नेता कड़ाके की ठण्ड में भारी बर्फबारी से घबराये बिना दावोस पहुंचते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं यह लालच भी रहता है कि इस बहाने वह धरती पर स्वर्ग का जाड़े के मौसम में भी थोड़ा बहुत सुख भोग लेंगे।

5. चूंकि दावोस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वालों में अधिकांश- लगभग सत प्रतिशत- पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक होते हैं, इसीलिए दावोस सम्मेलन को बहुत आसानी से विश्व बैंक और आई.एम.एफ का समर्थन भी मिलता रहा है।

6. वास्तव में दावोस एक ऐसा ग़ैर सरकारी संगठन है जिसके सरोकार आम आदमी की जिंदगी से सीधे नहीं जुड़ते, बल्कि जिसका काम बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विश्वव्यापी अभियानों के लिये जमीन तैयार करना ही है। दावोस शिखर सम्मेलन के खर्च की भरपाई करने वाली एक हज़ार कंपनियां है, जिनमें से प्रत्येक प्रतिवर्ष एक लाख डॉलर का चंदा देती है। इनके स्वामी या सीईओ दावोस जाकर विश्व के प्रमुख राजनेताओं से सीधी मुलाकात और बातचीत का मौका हासिल कर सकते हैं। इनमें से अनेक ऐसी कंपनियों के मालिक या सीईओ होते हैं जिनकी कंपनियों का कारोबार दुनिया के अनेक विकासशील देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से कई गुना ज़्यादा होता है।

7. इनके अलावा कुछ ऐसे सहयोगी सदस्य- पर्यवेक्षक होते हैं जो पांच से दस हज़ार डॉलर देकर निमंत्रण प्राप्त करते हैं। इनके लिए दावोस की कुछ सार्वजनिक बैठके ही खुली होती है, बाकी वार्तायें या दावतें इनकी पहुंच से बाहर रहती है। आमंत्रित पत्रकारों को भी दो श्रेणियों में बांटा जाता है, इसी कारण यह टिप्पणी की गई है जैसी जाति व्यवस्था/वर्ण व्यवस्था दावोस में देखने को मिलती है, वैसी कही और नहीं।

8. जहां उद्योगपतियों को और उद्यमियों को यह लगता है कि वह करीब से देख-सुनकर उन राजनेताओं के बारे में अपनी राय बना सकते हैं, जिनके देशों में उन्होंने पूंजी निवेश करना है या बाजार तलाश करना है। वहीं राजनेताओं को यह मौका मिलता है कि वह अपने देश को आकर्षक बनाकर पेश कर सके और अपने लिये आर्थिक निवेश तकनीकी सहायता आदि जुटा सके।

9. राजनेताओं के लिए दावोस एक और अवसर भी सुलभ कराता है। यहां वह बिना किसी जबावदेही या जिम्मेदारियों के अपने बैरियों से 'अचानक' मुलाकात कर सकते हैं। दावोस सम्मेलन में ही इजराइल के सिमोन पैरेस की मुलाकात फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात से मध्यस्तों ने कराई थी और निश्चय ही दोनों शत्रु पक्षों के बीच तनाव घटाया जा सका था। इसी तरह नस्लवादी रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के प्रतिनिधि के साथ नेलसन मंडेला की बातचीत भी दावोस में ही कराई जा सकी थी।

10. दावोस सम्मेलन के आयोजकों का मानना है कि दावोस अन्तर्राष्ट्रीय संकट निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ समय पहले अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में अछूत समझे जाने वाले किमजांगउन को भी यहां आमंत्रित किया गया था। पर बाद में जब परमाणविक हथियारों के परीक्षण के बाद उनसे यह निमंत्रण वापस ले लिया गया तब से यह भावना दृढ़ हुई है कि यह मंच वास्तव में तटस्थ नहीं, बल्कि अमेरिका के दबाव में और पश्चिमी देशों के हित में ही काम करता है।

11. बीबीसी के एक पत्रकार के अनुसार दावोस बेशुमार अमीर और आत्ममुग्ध लोगों का एक ऐसा क्लब है जो यह समझता है कि उन्हीं की जानकारी और नुस्खों से विश्व निरंतर प्रगति कर सकता है, पर ऐसे आलोचकों की भी कमी नहीं जिनका मानना है कि दावोस उन शोषक-उत्पीड़क पूंजीपतियों का जमावड़ा है जिनकी मुनाफाखोर नीतियों ने विकासशील देशों में गरीबी बढ़ाई है- तानाशाह शासकों के द्वारा बाजार के हित में मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा दिया है और विश्वभर में पर्यावरण के विनाश की रफ्तार बढ़ाई है। दावोस की कुछ बैठकें और इसके द्वारा प्रायोजित छोटे-छोटे सम्मेलन दूसरे देशों में भी होते रहे हैं। मैलबर्न में आयोजित ऐसे ही एक सम्मेलन में आक्रामक आन्दोलनकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया था।

12. जो लोग विश्व व्यापार संगठन का विरोध करते हैं, उनको दावोस शिखर सम्मेलन उसी साजिश का हिस्सा लगता है। पर इस सब के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि दावोस शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने अपनी उपलब्धियों का विश्वभर में बड़ा जबर्दस्त प्रचार किया है। पिछले वर्ष चीन के राष्ट्र शी जिंगपिंग ने दावोस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ था कि अब यह मंच और भी अधिक अहम बन जायेगा। (हालांकि इस वर्ष शी वहां नहीं गये और उन्होंने यह संदेश दिया कि उनकी प्राथमिकताओं में दावोस नहीं)।

13. भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से इस वर्ष दावोस सम्मेलन का आरंभ हुआ और उनके दावोस पहुंचने के पहले ही भाजपा ने यह दावा कर डाला कि इस तरह का सम्मान पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है। कांग्रेस ने तत्काल इस बात को झुठलाया और यह कहां कि दावोस जाने का न्यौता डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी कई बार मिला था, पर वह गणतंत्र दिवस की व्यस्तता के कारण कभी इस सम्मेलन में सिरकत नहीं कर सके।

14. मोदी ने अपने घंटेभर लंबे भाषण में भारत की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों और योग जैसी विश्व विरासत का उल्लेख करने के साथ-साथ भारत की समसामयिक तकनीकी क्षमता और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को भी रेखांकित किया। इस भाषण के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती तथा पर्यावरण का संकट भी थे।

कुछ विश्लेषकों के अनुसार भाषण अनावश्यक रूप से लंबा था और कई बार ऐसा लग रहा था कि यह भाषण विदेशियों को नहीं स्वदेशी मतदाताओं को ही सम्बोधित कर रहा था। जो चीजें भारतीय स्रोताओं और दर्शकों को दोहराव वाली लग रही थी वह पहली बार सुनने वालों को अपने लिये उपयोगी ही समझी जा सकती है। आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में सभी राजनेता अपने देश की आकर्षक नुमाइश करते हैं और यह आर्थिक राजनय का एक महत्वपूर्ण अंग है। अत: सिर्फ इस आधार पर दावोस में मोदी के राजनय की आलोचना करना जायज़ नहीं लगता।

15. इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि दावोस में भाग लेने वाले बड़े राजनेताओं में भारत के प्रधानमंत्री अकेले नहीं थे। इस वर्ष दावोस के शिखर सम्मेलन का समापन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के भाषण से हुआ। जाहिर है कि कम से कम वह दावोस को अमेरिकी कंपनियों के हित में समझते हैं। विडंबना यह है कि जहां भारत के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देते हैं और भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए बाज़ार ढूढ़ रहे हैं, वहीं दावोस में पहुंचे अन्य महानुभाव अपने-अपने उत्पादों के लिये बाजार तलाश कर रहे हैं और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और चीन के अमेरिका में प्रवेश को लेकर आशंकित रहे हैं।

16. ट्रंप का भाषण उनकी चिरपरिचित शैली में बड़बोला और भड़काऊ था। उन्होंने जमकर उत्तरी कोरिया पर हमला बोला और मीडिया को गालियां दी। किसी के साथ भी सार्थक संवाद की कोई कोशिश इसमें नहीं थी। ट्रंप की अदूरदर्शी और प्रोटेक्सनिस्ट नीतियां दावोस के भू-मंडलीकरण समर्थक संस्कार के प्रतिकूल ही कही जा सकती है।

17. इसमें अचरज नहीं किया जाना चाहिए कि दावोस के सिलसिले में जो खबरे सुर्खियों में रही, वह सभी बराबर वज़न की नहीं समझी जा सकती। मसलन दावोस में मुकेश अंबानी ने लक्ष्मी मित्तल से मुलाकात की या फिर शाहरुखखान को उनके चाहने वालों की भीड़ ने कैसे घेर लिया। हमारी समझ में किसी भी खबर को पाठक या दर्शक तक पहुंचाने के लिए आज मीडिया उसे मनोरंजन का पुट देता है। इस बार भी यही हो रहा है।

18. भारतीय प्रधानमंत्री के दावोस वाले राजनय का सही मूल्यांकन करना इस कारण भी कठिन हो गया, क्योंकि पद्मावत फिल्म को लेकर उठे बवंडर ने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अभूतपूर्व मतभेद ने जनता का ध्यान अन्यत्र भटकाया। मोदी के आलोचकों को यह कहने का मौका मिला कि वह इन मुद्दों पर अपने मन की बात कहने से कतरा रहे थे और इसी कारण उन्होंने देश से बाहर रहना वाजिब समझा।

19. हमारी समझ में दावोस के बारे में किसी भी नतीजे पर पहुंचने के पहले भारत के समग्र आर्थिक राजनय की रणनीति को समझना परमावश्यक है- भारत दावोस में ही नहीं, जी-20, ब्रिक्स और शांघाई सहकार संगठन में भी सक्रिय है। वह आसियान के साथ अपने आर्थिक तकनीकी संबंधों को भी और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। दावोस इसका एक महत्वपूर्ण पर छोटा सा हिस्सा है।